TEXT OF SPEECH OF COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA SHRI G C MURMU AT ACCOUNTANTS GENERAL CONFERENCE TODAY

माननीय अध्यक्ष की उपस्थिति में

सीएजी का दूसरे दिन का अभिभाषण (17.11.2022 को)

1. माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, \ भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों, \ देवियों और सज्जनों ! \

2. महालेखाकारों का 30वां द्विवार्षिक सम्मेलन समाप्त होने जा रहा है \ और इसके साथ ही मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि \ सम्मेलन के व्यापक विषय- साई इंडिया:, उन्नति की ओर अग्रसर भारत में \ योगदान के अंतर्गत चर्चा के लिए चुने गए विषयों पर कई रचनात्मक और व्यावहारिक सिफारिशें की गई। \ मैं जीवंत बहस और चर्चाओं के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। \

3. संवैधानिक शासन के केंद्रीय सिद्धांतों में से एक यह सुनिश्चित करना है कि\ नीतिगत कार्यों के सार्वजनिक खर्चों का हिसाब रखा जाए। \ एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के स्वतंत्र निरीक्षण प्राधिकारी के रूप में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कर्तव्य \ न केवल कार्यपालिका द्वारा तैयार किए गए वित्तीय लेखाओं को विधायिका के लिए सुलभ बनाना है, \ बल्कि यह भी उजागर करना है कि \ कार्यपालिका द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रमों \ और परियोजनाओं को कैसे कार्यान्वित किया जाता है। \

4. भारत के संविधान में परिकल्पित है कि \ सीएजी का पद विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र है। \ साथ ही, \ सीएजी को महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार की \ दोनों शाखाओं के साथ लगातार संपर्क में रहना चाहिए। \ कार्यपालिका पर संसदीय निगरानी बड़े पैमाने पर सीएजी द्वारा तैयार की गई लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर निर्भर करती है। \ हमारा मुख्य कार्य न केवल तथ्यों और आंकड़ों की जांच करना, \ और गुणवत्ता लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करना है, \ बल्कि लेखापरीक्षा प्राथमिकता के लिए प्रासंगिक मुद्दों का चयन करना भी है। \ हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि \ संसदीय समितियों के कार्यों और हमारी अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्टों में \ यथासंभव सामंजस्य और समन्वय किया गया है।\ कार्यपालिका पर प्रभावी संसदीय निगरानी सुनिश्चित करने के लिए \ यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। \

5. महात्मा गांधी जी के \ उन ज्ञान से परिपूर्ण शब्दों को याद करना उचित होगा \ जब उन्होंने कहा था \ "... हमें हमेशा जागृत, सतर्क एवं प्रयासरत रहना होगा...।\ यह भावना आज भी दुनिया भर के संसदीय लोकतंत्रों के संदर्भ में समान रूप से लागू होती है। \ सरकारें अपने घटकों की सामाजिक-आर्थिक मांगों को पूरा करने में \ पर्याप्त सार्वजनिक धन को सम्मिलित करते हुए \ बड़े पैमाने पर परिवर्तनकारी हस्तक्षेप करती हैं। \ इसलिए, \ यह सुनिश्चित करना काफी महत्वपूर्ण है कि \ इन विभिन्न सार्वजनिक योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ \ वास्तव में अभीष्ट लक्षित समूहों और सेक्टरों तक पहुंच रहा है। \

6. इस संबंध में हम जो निरीक्षण करते हैं, \ विशेष रूप से विभिन्न सार्वजनिक सहभागिताओं की निष्पादन लेखापरीक्षा के माध्यम से किया गया निरीक्षण, \ वह न केवल \ सरकारी व्यय की संसदीय जांच के लिए महत्वपूर्ण है, \ बल्कि कार्यपालिका के लिए भी सुधारात्मक कार्रवाई करने \ और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि \ अपेक्षित परिणाम पूर्ण रूप से प्राप्त किए गए हैं। \ हमारी निष्पादन लेखापरीक्षाएं ऐसी सहभागिताओं की अर्थव्यवस्था, \ कार्यकुशलता और प्रभावशीलता पर उपयोगी विचार प्रदान करती हैं, \ जो अंततः विधायी जांच को मजबूत बनाने में योगदान देते हैं । \

7. निश्चित रूप से, \ लेखापरीक्षा कार्य संघटित रूप से विकसित होना चाहिए, \ और सभी हितधारकों को सौंपी गई जिम्मेदारियों को \ निष्पादित करने के लिए शामिल करने में सक्षम होना चाहिए। \ इस संदर्भ में, \ मुझे सम्मेलन में चर्चा के लिए उठाए गए विषयों की \ व्याख्या करते हुए प्रसन्नता हो रही है। \

8. 15वें वित्त आयोग ने \ 2021 और 2026 के बीच की पांच साल की अवधि के लिए \ विधिवत गठित स्थानीय सरकारों के विभिन्न कार्यक्रमों की सहायता

करने के लिए \ 4,36,361 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है। \ देश भर में इस विशाल सार्वजनिक निधि वितरण को ध्यान में रखते हुए, \ हमारी चर्चा का एक विषय \ स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा को सुदृढ़ करने से संबंधित था। \ यह एक महत्वपूर्ण कदम है, \ क्योंकि यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि \ अनुदानों का उचित उपयोग किया गया है \ तथा कार्यक्रमों और योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। \ इसलिए, \ स्थानीय निकायों की हमारी लेखापरीक्षाओं को यह सत्यापित करने की आवश्यकता है कि \ क्या आयोग द्वारा सिफारिश किए गए महत्वपूर्ण राजकोषीय सोपान, \ जैसे कि \ (i) राज्य वित्त आयोगों की स्थापना / (ii) इसकी सिफारिशों पर कार्य करना \ (iii) संबंधित राज्य विधानमंडलों को की गई कार्रवाई को प्रस्तुत करना \ (iv) स्थानीय निकायों के लेखाओं को सार्वजनिक डोमेन में रखना और \ (v) संपत्ति करों के लिए न्यूनतम दरें निर्धारित करना आदि \ पूरे कर लिए गए है। \ **स्थानीय सरकारी प्राधिकारियों** को स्वतंत्र रूप से यह सत्यापित करने की भी आवश्यकता होगी कि \ क्या बुनियादी सामाजिक सेवाओं जैसे स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्ति लक्ष्य को पूरा करना, \ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, \ पेयजल व्यवस्था, \ वर्षा जल का संचयन और \ जल पुनर्चक्रण के लिए प्रदान किए गए अनुदान को \ सिफारिश किए गए उद्देश्यों के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है। \

9. सम्मेलन का एक और विषय \ 'सामाजिक रूप से प्रासंगिक' लेखापरीक्षाओं की पहचान करने से संबंधित था। \ बड़ी संख्या में सरकारी सहभागिता का महत्त्व \

हमारे समाज के सबसे वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए है। \ इन कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित करने \ और तदनुसार लेखापरीक्षा समीक्षाओं को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। \ इससे सरकार के साथ-साथ\ संसद दोनों को कम निष्पादन वाले क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी \ और यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि पहचान की गई कमियों को दूर करने पर \ कार्यकारी महत्त्व को जल्द से जल्द और प्रभावी ढंग से निपटाया गया है।\

10. वर्तमान समय में शासन का क्षेत्र तेजी से और जटिल परिवर्तनों से गुजर रहा है। \ इसकी अपनी चुनौतियां हैं। \ हम सार्वजनिक नीति समाधान प्रदान करने के लिए \ सार्वजनिक सेवा वितरण और जटिल आईटी प्लेटफार्मों के प्रयोग में कई कार्यकर्ताओं की भागीदारी देखते हैं। \ यह अपरिहार्य है कि \ हमें भी इन चुनौतियों को समझना \ और आत्मसात करना होगा, \ और तदनुसार विकसित करना होगा। \ मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि \ हमने अपने डेटा विश्लेषिकी कौशल को निखारकर \ और देश के प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए विशेष लेखाकरण मॉडल डिजाइन करके \ इस दिशा में कुछ पहलें की हैं। \

11. इस सम्मेलन का अगला विषय \ राज्य वित्त की स्थिरता पर रिपोर्टिंग में सुधार करना था। \ भारतीय राज्यों की राजकोषीय स्थिति एक प्रासंगिक मुद्दा है\ जिसका सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए।\ हमारे राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में\ हम लगातार जोखिम कारकों \ जैसे कि प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि,\ बकाया सार्वजनिक ऋण और देनदारियों में वृद्धि, \ कर और गैर-कर स्रोतों से राजस्व सहित अपने संसाधनों का कम जुटाया जाना \ और राजस्व संग्रह में उच्च बकाया, \ को उजागर कर रहे हैं \ जो राज्य के वित्त को प्रभावित करते हैं।\ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत \ विभिन्न मापदंडों में घाटे की नकारात्मक प्रवृत्ति, \ मध्यम अवधि के राजकोषीय योजना लक्ष्यों को प्राप्त न करना \ अन्य चिंताओं में से एक है। \

12. हमारे राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, \ घटक-वार ऋण प्रवृत्तियों, राज्यों के राजकोषीय घाटे के घटकों \ और विभिन्न राज्यों की ऋण परिपक्वता प्रोफाइल से संबंधित मुद्दों के संबंध में \ गहन विश्लेषण किया गया है। \ हम ऋण स्थिरता संकेतकों और प्रवृत्तियों पर भी \ रिपोर्ट प्रदान कर रहे हैं। \ भारतीय रिजर्व बैंक और 15वें वित्त आयोग ने भारतीय राज्यों के लिए \ राजकोषीय जोखिमों के संभावित स्रोतों पर भी ध्यान दिया है,\ जिसमें स्वयं के कर राजस्व में गिरावट,\ कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजनाओं को फिर से शुरू करना,\ घाटे में चल रही बिजली वितरण कंपनियों के बढ़ते बकायों \ और कृषि ऋण माफी तथा सब्सिडी का आवधिक वितरण शामिल है।\

13. ऐसे अन्य मुद्दे भी हैं \ जिन्हें मैं यहां उजागर करना चाहता हूं। \

14. प्रणालीगत निरीक्षण को सूक्ष्म-स्तरीय निरीक्षण के साथ संतुलित करने की तत्काल आवश्यकता है, \ ताकि प्रणाली स्तर पर कार्यकारी हस्तक्षेपों के समग्र निर्धारण \ और सूक्ष्म-स्तर पर विचलित कार्यकारी कार्रवाई से निवारण के बीच\ संतोषजनक संतुलन पर पहुंचा जा सके। \

15. हम सूक्ष्म स्तर पर नियमों और विनियमों से विचलन देखते हैं, \ जिसे कार्यपालिका के साथ-साथ संसद के ध्यान में लाया जा सकता है \ ताकि संबंधित पदाधिकारियों पर यथाशीघ्र उत्तरदायित्व जिम्मेदारियां तय की जा सकें। \ पारंपरिक अनुपालन लेखापरीक्षा \ और निष्पादन लेखापरीक्षा दोनों में, \ वैज्ञानिक जोखिम विश्लेषण \ और विश्लेषणात्मक साधनों के आधार पर स्पष्ट उद्देश्यों को \ अनुकूलित करने \ और सभी क्षेत्रीय लेखापरीक्षकों को प्रसारित करने की आवश्यकता है। \

16. द्वितीय, \ सीएजी की निगरानी के माध्यम से संसदीय संवीक्षा सुनिश्चित करने के लिए \ लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों सहित \ सभी अभिलेखों तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करना है। \ इस ई-गवर्नेंस युग में \ इसका बहुत महत्व है, \ जिसमें डेटा का बड़ी संख्या में डिजिटलीकरण किया जा रहा है। \ गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के संबंध में \ यदि कोई, चिंताएं हों, तो उनका उपयुक्त तौर-तरीकों की कार्यप्रणाली के माध्यम से \ निस्संदेह निवारण किया जा सकता है। \ समयबद्ध तरीके से अभिलेखों तक पहुंचने में हमें किसी भी बाधा को दूर करने के लिए \ संबंधित विभागों के साथ सक्रिय रूप से कार्य करने की भी आवश्यकता है, \ ताकि कार्यकारी कार्रवाई की संवीक्षा करने का \ संसदीय अधिदेश किसी भी तरह से प्रभावित न हो। \

17. तीसरा, \ हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में लगातार अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने \ और हमारी पेशेवर क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है, \ जबकि लेखापरीक्षा प्रथाओं की अंतर्निहित सामर्थ्य को बनाए रखते हुए, \ जिन्हें हमने वर्षों से अपनी लेखापरीक्षा पद्धतियों में विकसित और शामिल किया है। \

18. चौथा, \ यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं है कि \ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सभी स्तरों पर जटिल हो गया है, \ विवेकपूर्ण प्रबंधन यह सुनिश्चित करने के लिए

महत्वपूर्ण है कि \ सार्वजनिक संसाधनों का समयबद्ध तरीके से कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाए \ और सरकारी खजाने के लिए धन की अधिकतम राशि उपलब्ध हो। \ सुपरिभाषित लेखापरीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से \ यथासमय प्राप्त फीडबैक उपयोगी फीडबैक प्रदान करता है। \ इसलिए कार्यपालिका और लेखापरीक्षा के बीच संबंध रचनात्मक होना चाहिए। \

19. मुझे विश्वास है कि पिछले दो दिनों के दौरान हुए विचारों \ और अनुभवों के सहभाजन से \ हमारी मौजूदा लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और पद्धतियों को सुव्यवस्थित करने में वृद्धि होगी, \ और इस प्रकार, \ इस देश के शासन में सुधार होगा। \ मैं आज हमारे भारत के सबसे बड़े नेताओं में से एक \ लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जी के एक प्रेरणादायक उद्धरण के साथ \ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, \ जिसमें उन्होने ने कहा है कि: \ "हम सामान्य प्रयासों से, देश को एक नई महानता की ओर ले जा सकते हैं।" \

धन्यवाद

जय हिंद